अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

One India, One Emergency Number 112

रजि.न.34300/80 | संख्या 11 | श्री विजय पुरम, रविवार, 11 जनवरी 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से अण्डमान तथा निकोबार में विकास की लहर

अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट–राष्ट्रीय महत्व की परियोजना : अरूण सिंह

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में मेगा अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु कई हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे आने वाले वर्षों में क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आने की उम्मीद है। इन पहलों से द्वीपवासियों को उल्लेखनीय लाभ मिलेगा और द्वीपसमूह सतत आर्थिक विकास के मार्ग पर सु.ढ़ रूप से अग्रसर होगा। यह बात आज यहां मीडिया से बातचीत के दौरान माननीय राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह ने कही।

प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालते हुए माननीय सांसद ने बताया कि कैंपबेल बे में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) राष्ट्रीय महत्व की एक प्रमुख रणनीतिक परियोजना है। उन्होंने हाल के वर्षों में पूर्ण की गई कई ऐतिहासिक परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनसे द्वीपवासियों को व्यापक लाभ हुआ है, जिनमें समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल (सीएएएनआई) परियोजना का शुभारंभ, आज़ाद हिंद सेतु तथा वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण शामिल है।

द्वीपसमूह की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री अरुण सिंह ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदानों के कारण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने 'तीर्थ स्थल' का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनेक अज्ञात नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीजी–जी राम जी योजना का उल्लेख करते हुए माननीय सांसद ने बताया कि यह 'विकसित भारत' की परिकल्पना का हिस्सा है, जिसे जी राम जी अधिनियम, 2025 के माध्यम से लागू किया गया है और जो मनरेगा का स्थान लेती है। यह नया परिकल्पना ग्रामीण रोजगार के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, रोजगार सृजन को टिकाऊ अवसंरचना निर्माण से जोड़ना, विकसित ग्राम पंचायतों के माध्यम से डिजिटल योजना को सशक्त बनाना तथा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप तेज और अधिक पूर्वानुमेय मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि इस योजना को अधिक जनहितैषी बनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। परिसंपत्ति सृजन पर विशेष जोर देते हुए यह योजना उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है तथा केंद्र–राज्य वित्तपोषण मॉडल को अपनाती है। यह योजना चार प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन को अवसंरचना विकास से जोड़ने के लिए तैयार की गई है, जिनमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना तथा अत्यधिक मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य शामिल हैं।

प्रारूप मतदाता सूची–2026 का प्रकाशन

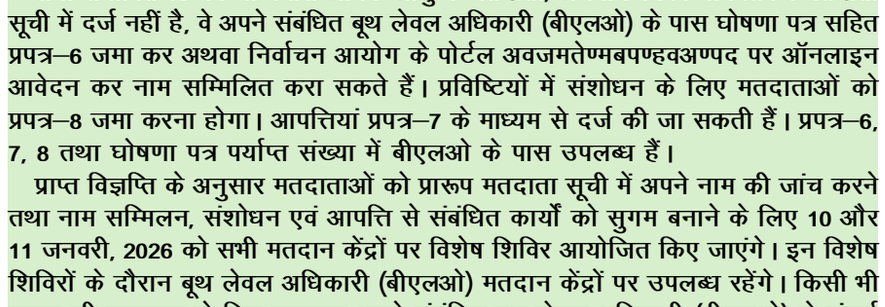

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने सूचित किया है कि विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) के लिए प्रारूप मतदाता सूची–2026 का प्रकाशन 23 दिसंबर, 2025 को किया गया। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 22 जनवरी, 2026 तक निर्धारित है।

सभी संभावित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता, अथवा जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास घोषणा पत्र सहित प्रपत्र–6 जमा कर अथवा निर्वाचन आयोग के पोर्टल अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद पर ऑनलाइन आवेदन कर नाम सम्मिलित करा सकते हैं। प्रविष्टियों में संशोधन के लिए मतदाताओं को प्रपत्र–8 जमा करना होगा। आपत्तियां प्रपत्र–7 के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। प्रपत्र–6, 7, 8 तथा घोषणा पत्र पर्याप्त संख्या में बीएलओ के पास उपलब्ध हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने तथा नाम सम्मिलन, संशोधन एवं आपत्ति से संबंधित कार्यों को सुगम बनाने के लिए 10 और 11 जनवरी, 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन विशेष शिविरों के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं अथवा मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

"आइलैंड सी–फूड फेस्टिवल–2026" का आयोजन

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग द्वारा सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से 15 एवं 16 जनवरी, 2026 को मरीना पार्क स्ट्रेच रोड, श्री विजय पुरम में "आइलैंड सी–फूड फेस्टिवल–2026" का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में टूना क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आइलैंड सी–फूड फेस्टिवल के अंतर्गत मत्स्य विभाग पुरुष एवं महिला वर्ग में "शेफ प्रतियोगिता" के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक प्रतिभागी अपने घर पर समुद्री भोजन (सी–फूड) से बने व्यंजन तैयार कर 15 जनवरी, 2026 को महोत्सव स्थल पर निर्धारित स्थान पर अपने द्वीपीय सी–फूड व्यंजनों का प्रदर्शन कर सकते हैं। व्यंजनों का मूल्यांकन निर्णायक मंडल द्वारा तैयारी एवं प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा तथा विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

इच्छुक प्रतिभागी अपनी सहभागिता की सहमति व्यक्तिगत रूप से सहायक निदेशक (मत्स्य) (मुख्यालय–2), मत्स्य निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, लॉ कॉलेज के सामने, मोहनपुरा, श्री विजय पुरम–744101 में या फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर–8900973237 पर संपर्क किया जा सकता है।

मत्स्य विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुरूष एवं महिला शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने की सहमति जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी, 2026 को अपराह्न 3 बजे तक है।

राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग, जेएनआरएम, एनवाईके, साई तथा रामकृष्ण मिशन के सहयोग से 12 जनवरी, 2026 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 7.15 बजे जेएनआरएम परिसर में आयोजित होगा।

प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समारोह के अंतर्गत एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 900 छात्र–छात्राएं/अधिकारी भाग लेंगे। रैली सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम से प्रारंभ होकर नेताजी स्टेडियम–घंटा घर–डाकघर–बंगाली क्लब–सीईओ कार्यालय–एलआईसी भवन के सामने–गांधी प्रतिमा–घंटा घर–नारायण चौक–स्विमिंग पूल–गर्ल्स स्कूल–आरके मिशन होते हुए जेएनआरएम स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर समाप्त होगी।

प्रौद्योगिकी एकीकरण पर तीन दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम का समापन

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

"प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से मूलभूत शिक्षा के शिक्षकों को प्रमुख संसाधन व्यक्ति (केआरपी) के रूप में सशक्त बनाना: टैबलेट के माध्यम से कक्षा शिक्षण को सुदृढ़ करना" विषय पर आयोजित तीन दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह 9 जनवरी, 2026 को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, मिडिल प्वाइंट के ऑडिटोरियम, श्री विजय पुरम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का आयोजन कक्षा शिक्षण में प्रौद्योगिकी के समावेशन के माध्यम से मूलभूत शिक्षा के शिक्षकों को प्रमुख संसाधन व्यक्ति (केआरपी) के रूप में सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर श्रीमती संगीता चंद, प्राचार्या, राज्य शिक्षा संस्थान/डाइट ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल को अपने–अपने विद्यालयों, क्लस्टरों तथा शैक्षिक क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रसारित करने का आह्वान किया, ताकि इसका व्यापक शैक्षणिक प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

प्रो. इंदु कुमार, प्रमुख, प्रशिक्षण एवं आईसीटी विभाग, सीआईईटी–एनसीईआरटी ने अपनी टीम के साथ कार्यक्रम के दौरान रोचक एवं व्यावहारिक सत्रों का संचालन किया। उन्होंने

शेष पृष्ठ 4 पर

रंगत में जनभागीदारी के साथ समुद्री तट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

रंगत, 10 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वर्ष 2025–2026 के कार्यक्रम कैलेंडर के अंतर्गत समुद्री तट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ आज निम्बूतला स्थित रमण बगिचा समुद्री तट पर किया गया। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन पंचायत समिति रंगत की प्रमुख श्रीमती सीता मांझी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, रंगत तहसील के प्रधान, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय एवं पर्यटक उपस्थित रहे। इसका आयोजन सहायक आयुक्त, मिडिल अण्डमान, रंगत के कार्यालय द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्य अतिथि ने स्प्रिंट प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

शेष पृष्ठ 4 पर

महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसबीआई–आरसेटीआई), श्री विजय पुरम द्वारा आयोजित 20 दिवसीय पापड़, अचार एवं मसाला पाउडर निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में 'डीब्राइट' की संकाय सदस्य श्रीमती समीमा बेगम तथा एनसीएफटी की श्रीमती मीना, संसाधन विशेषज्ञों के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने पापड़, अचार एवं मसाला पाउडर निर्माण संबंधी

शेष पृष्ठ 4 पर

परीक्षा पे चर्चा: अब तक 4 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों ने कराया पंजीकरण

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या चार करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार 9 जनवरी तक 4 करोड़ 20 लाख 69,002 लोगों ने परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।

देश–विदेश से करोड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। न केवल छात्र बल्कि लाखों की संख्या में अभिभावक और शिक्षक भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में शामिल होना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए 'परीक्षा पे चर्चा' एक बहुप्रतीक्षित संवाद कार्यक्रम है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के संवाद में छात्रों के साथ–साथ उनके माता–पिता और शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां होने वाले संवाद के जरिए अभिभावक व शिक्षक छात्रों को उनके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में बेहतर सहयोग दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' का उद्देश्य परीक्षाओं से जुड़े तनाव को कम करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और पढ़ाई को एक सकारात्मक अनुभव बनाना है। यह कार्यक्रम परीक्षा को डर नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविकास का अवसर मानने की सोच को प्रोत्साहित करता है। एक विशेष प्रक्रिया के जरिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का चयन होता है। प्रधानमंत्री छात्रों में परीक्षा का तनाव दूर करने और उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए यह विशेष संवाद करते हैं।

यही कारण है कि 'परीक्षा पे चर्चा' के इस संवाद में देश भर के छात्र शामिल हो रहे हैं। अब तक चार करोड़ बीस लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम यानी परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) का यह 9वां संस्करण है। यह संवाद इसी महीने जनवरी में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारत समेत विश्व के कई देशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। देश के किसी भी हिस्से से क्लास 6 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुक्रवार तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 3 करोड़, 91 लाख, 50,348 रजिस्ट्रेशन देश–दुनिया के विभिन्न इलाकों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा करवाए गए हैं।

वहीं, 23 लाख 62 हजार 202 शिक्षक भी अभी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनके अलावा अभी तक 5 लाख 56 हजार 452 अभिभावकों ने भी अपना पंजीकरण कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पंजीकरण करवाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यह विशेष संवाद छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक साथ लाकर परीक्षाओं को सीखने के उत्सव में बदलने का प्रयास करता है।

हाइपरसोनिक मिसाइल से संबंधित महत्वपूर्ण ग्राउंड परीक्षण हुआ सफल

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (डीआरडीएल) की सहायता से हासिल की गई है।

दरअसल, डीआरडीएल ने सक्रिय शीतलन युक्त पूर्ण–स्तरीय स्क्रैमजेट इंजन (फुल स्केल कंबस्टर) का दीर्घ–अवधि ग्राउंड परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। डीआरडीएल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की हैदराबाद स्थित अग्रणी प्रयोगशाला है। इस सफल परीक्षण ने भारत को उन्नत एयरोस्पेस क्षमताओं की वैश्विक अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षण 09 जनवरी को डीआरडीएल की अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा में किया गया।

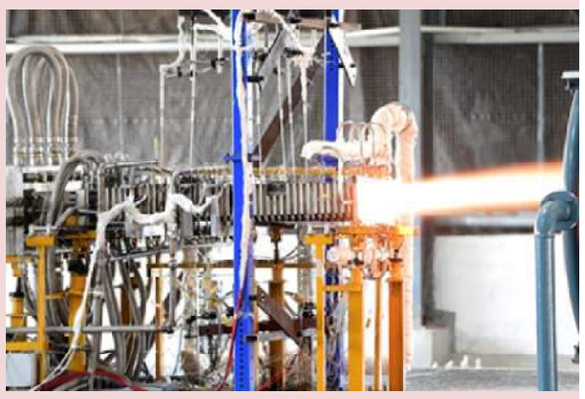

रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसने स्क्रैमजेट दहनकक्ष ने 12 मिनट से अधिक समय तक निरंतर और स्थिर संचालन प्रदर्शित किया। यह उपलब्धि भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक निर्णायक और आधारभूत कदम मानी जा रही है।

गौरतलब है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से पांच गुना से अधिक, अर्थात 6,100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रतार से लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम होती है। यह असाधारण क्षमता अत्याधुनिक एयर–ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

यह सुपरसोनिक दहन तकनीक का उपयोग कर दीर्घ–अवधि तक निरंतर प्रणोदन (मिसाइल को आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न की जाने वाली शक्ति) प्रदान करता है। स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा में किए गए इन ग्राउंड परीक्षणों ने उन्नत स्क्रैमजेट दहनकक्ष के डिजाइन को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया है।

साथ ही देश की अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना और तकनीकी दक्षता को भी प्रमाणित किया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि शुक्रवार को मिली यह कामयाबी बीते साल 25 अप्रैल को किए गए दीर्घ–अवधि के सब–स्केल परीक्षण पर आधारित है। उस परीक्षण ने इस उन्नत प्रौद्योगिकी के क्रमिक और सुदृढ़ विकास को सुनिश्चित किया है। पूर्ण–स्तरीय स्क्रैमजेट दहनकक्ष और परीक्षण सुविधा का डिजाइन एवं विकास डीआरडीएल द्वारा किया गया। वहीं, इसके निर्माण और कार्यान्वयन में भारतीय उद्योग साझेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग साझेदारों और शैक्षणिक संस्थानों को बधाई दी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक मजबूत और ठोस आधार प्रदान करती है।

उन्होंने बताया कि यह देश की सामरिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वहीं, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने भी इस परीक्षण से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और तकनीकी टीमों को उनके सराहनीय योगदान के लिए शुभकामनाएं दीं। इस सफल ग्राउंड परीक्षण के साथ भारत ने हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर लिया है।

प्रौद्योगिकी एकीकरण पर तीन दिवसीय ——————————पृष्ठ 1 का शेष

दीक्षा, ई–पाठशाला, ई–जादुई पिटारा तथा पीएम ई–विद्या चैनलों जैसे विभिन्न राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को कैनवा, स्टॉप मोशन एनीमेशन टूल्स तथा एआई आधारित टूल्स जैसे नवोन्मेषी अनुप्रयोगों से भी परिचित कराया गया, जिससे मूलभूत कक्षाओं में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा

सके। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ हुआ। उन्होंने डिजिटल टूल्स के व्यावहारिक अनुभव की सराहना की तथा बेहतर अधिगम परिणामों के लिए कक्षा शिक्षण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को लेकर अपना आत्मविश्वास व्यक्त किया।

रंगत में जनभागीदारी के साथ समुद्री तट ——————————पृष्ठ 1 का शेष

इस बीच खेल महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर 14 एवं 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं तथा सभी पुरुष एवं महिलाओं के लिए विभिन्न समुद्र तटीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। खेल विधाओं में बीच स्प्रिंट, रस्सी कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी, फुटबॉल, रस्साकशी, म्यूज़िकल चेयर, संगीत के साथ बॉल पास करना तथा टेनिकोइट (सिंगल्स) शामिल हैं। इन खेल प्रतियोगिताओं का संचालन शिक्षा विभाग, रंगत के सहयोग से किया जा रहा है।

इससे पूर्व श्री रमेश कुमार, तहसीलदार रंगत ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जानकारी दी। आज प्रारंभ हुआ यह आयोजन कल 11

जनवरी को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न होगा।

महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने ——————————पृष्ठ 1 का शेष

जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे आने पर प्रशिक्षुओं की सराहना की तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की सलाह दी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की 30 महिला प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। एसबीआई आरसेटीआई से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समापन समारोह का समापन एसबीआई–आरसेटीआई के संकाय सदस्य श्री पी. कलिस्वरन द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा कार्बाइंस कोव समुद्री तट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ने आज दोपहर 2.30 बजे मनमोहक कार्बाइंस कोव समुद्र तट पर बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट के भव्य फाइनल का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस रोमांचक खेल आयोजन के साथ शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीमवर्क और सामुदायिक सौहार्द का उत्सव मनाया गया।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की एक प्रमुख सामुदायिक संपर्क पहल के रूप में दिनांक 7 जनवरी, 2025 को यह टूर्नामेंट पहली बार प्रारंभ किया गया। यह पहल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय पुलिस महानिदेशक के दूरदर्शी मार्गदर्शन में परिकल्पित की गई थी। इस आयोजन का उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा पुलिस–जनता के बीच सकारात्मक संवाद को सुदृढ़ करना था। टूर्नामेंट सभी के लिए खुला था और इसमें कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया, जिससे व्यापक और समावेशी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हुई।

फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गीता रानी वर्मा (आईपीएस), पुलिस महानिरीक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में श्री ए. कोन (आईपीएस), उप पुलिस महानिरीक्षक, श्रीमती नियति मित्तल कश्यप, पुलिस अधीक्षक (एपीयू), श्री विकाश (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री रजनीकांत अवधिया, उप पुलिस अधीक्षक (एपीयू) सहित अन्य पुलिस अधिकारी, खेल प्रेमी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिससे आयोजन की रौनक और बढ़ गई।

नॉकआउट प्रारूप में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में पुलिस टीम ने सेवा भारत टीम को पराजित कर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की और सेवा भारत टीम उप विजेता रही। दोनों टीमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना के लिए पदकों से सम्मानित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती गीता रानी वर्मा (आईपीएस) ने सभी प्रतिभागी टीमों के प्रयासों की सराहना की तथा खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने में पुलिस कर्मियों की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं सौहार्द को भी मजबूत करती हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार टूर्नामेंट का समापन उत्साह, खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के वातावरण में सम्पन्न हुआ, जो इस सामुदायिक पहल की सफलता को दर्शाता है। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ने खेल, स्वास्थ्य, युवा सहभागिता और सामुदायिक एकता को प्रोत्साहित करने तथा द्वीपसमूह में पुलिस–जनता के सकारात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

व्यावहारिक शिक्षण पहल में छात्रों का अध्ययन भ्रमण

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गाराचरामा के लगभग 200 विद्यार्थियों ने 7 जनवरी, 2026 को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा आयोजित एक शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण के तहत डेयरी प्रशिक्षण–सह–प्रदर्शन फार्म तथा सरकारी केंद्रीय हैचरी, एलएफसी, डॉलीगंज का भ्रमण किया।

विद्यार्थियों को मार्गदर्शित भ्रमण के लिए विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें उन्होंने कैटल फार्म, बकरी इकाई, सुअर पालन अनुभाग, चारा अनुभाग तथा अत्याधुनिक हैचरी सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पशु आवास प्रणालियां, प्रजनन पद्धतियां, आहार प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल प्रोटोकॉल तथा अंडों के ऊष्मायन, चूजों के निकलने और उनके पालन की संपूर्ण प्रक्रिया को देखा।

पशु चिकित्सकों एवं तकनीकी कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को पशुधन एवं कुक्कुट पालन में अपनाई जाने वाली आवश्यक वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों की जानकारी दी। प्रमुख विषयों में संतुलित आहार निर्माण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीकें, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार, नियमित टीकाकरण एवं कृमिनाशन कार्यक्रम, जैव–सुरक्षा उपाय, कंपोस्टिंग के माध्यम से अपशिष्ट का उपयोग, इनक्यूबेटर का संचालन, तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रण तथा द्वीपसमूह के किसानों को गुणवत्तापूर्ण चूजे एवं बत्तख के बच्चे उपलब्ध कराने में हैचरी की भूमिका शामिल थी।

विद्यार्थियों ने गहरी जिज्ञासा का प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों से सक्रिय संवाद किया और पशु पोषण, रोग निवारण, हैचिंग क्षमता में सुधार तथा पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में कॅरियर की संभावनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे। अनेक विद्यार्थी विशेष रूप से स्वचालित ऊष्मायन प्रक्रिया और नवजात चूजों को देखकर अत्यधिक उत्साहित दिखे।

साथ आए शिक्षकों ने कक्षा शिक्षण को पूरक बनाने वाली तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में रुचि जागृत करने वाली इस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षण पहल के आयोजन के लिए विभाग की सराहना की।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने बताया कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण द्वीपीय परिस्थितियों के अनुरूप सतत् एवं वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों के प्रति युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा उन्हें पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में कॅरियर अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभाग के सतत् शैक्षणिक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी महीनों में और अधिक विद्यालयों के लिए डीटीसीडीएफ, डॉलीगंज तथा केंद्रीय हैचरी के भ्रमण निर्धारित किए गए हैं।

स्काई शो का आयोजन

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

विज्ञान केंद्र, श्री विजय पुरम में आज शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक "स्काई शो" का आयोजन करेगा। प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम में ग्रह–बृहस्पति और शनि के बारे में विवरण शामिल है। ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का पता लगाने के लिए आगंतुकों को श्री विजय पुरम के आकाश का एक आकाश मानचित्र प्रदान किया जाएगा। आगंतुक को शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से ग्रह–शनि और उसके विशाल छल्लों को देखने का रोमांचक अनुभव भी मिल सकता है, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नाम से जाना जाता है और ग्रह–बृहस्पति और उसके उपग्रहों को भी देखा जा सकता है। स्काई शो के लिए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 10 रूपए है।

विज्ञान केंद्र की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शाम 6.15 बजे एक बबल शो और शाम 5.30 बजे और 6.10 बजे विशेष 3डी शो होगा। बबल शो और 3डी शो के लिए प्रवेश शुल्क प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रति व्यक्ति 10 और 20 रुपये है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) एस. बिजू पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

बाल विवाह के खिलाफ भारत का ऐतिहासिक मिशन, 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद, बाल विवाह भारत में एक व्यापक सामाजिक चुनौती बना हुआ है, जो देश भर में लाखों युवकों और युवतियों को प्रभावित कर रहा है। यह युवा लड़कियों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों, खासकर कम उम्र में गर्भधारण, घरेलू हिंसा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और गरीबी तथा लैंगिक असमानता के दुष्चक्र को कायम रखता है। भारत में प्रगति के बावजूद, 20–24 वर्ष की आयु की 23 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5, 2019–21)। यह बाल विवाह को एक निरंतर खतरा और एक जघन्य अपराध के रुप में पेश करता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे राज्य बाल विवाह की सबसे अधिक घटनाओं वाले राज्यों में से हैं, लेकिन पूरे देश में बाल विवाह के छिटपुट मामले सामने आते रहे हैं।

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत परिभाषित बाल विवाह, ऐसा कोई भी संबंध है, जिसमें महिला/लड़की 18 वर्ष से कम आयु की और पुरुष 21 वर्ष से कम आयु का हो। यह विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के दुष्चक्र को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, भारतीय कानून के तहत बाल विवाह प्रत्यक्ष रूप से बाल बलात्कार के समान है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किसी पुरुष द्वारा किया गया कोई भी यौन कृत्य बलात्कार माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि जब कोई पति बाल विवाह के दौरान अपनी 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाता है, जो बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत दंडनीय अपराध है।

भारत में बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष

भारत में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास 19वीं शताब्दी में ही शुरू हो गए थे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप 1891 में सहमति के लिए आयु अधिनियम और बाद में 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम (शारदा अधिनियम) लागू हुआ, जिसमें लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। आज़ादी के बाद, सरकार ने 1948 के संशोधन (लड़कियों के लिए 15 वर्ष), 1978 के संशोधन (लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष) और अंत में 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम (महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष) के ज़रिए इन सीमाओं को बढ़ाया। कानूनी उपायों के साथ–साथ, देश भर में कई जागरूकता अभियान भी गति पकड़ने लगे, जैसे केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान (2015 से), जिनका मकसद सामाजिक मानसिकता को बदलना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और समुदायों को बाल विवाह की रिपोर्ट करने और उसका विरोध करने के लिए सशक्त बनाना था।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, ने बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 (शारदा अधिनियम) का स्थान लिया, जिसका मकसद बाल विवाहों को केवल नियंत्रित करने के बजाय पूरी तरह से प्रतिबंधित करना और पीड़ितों को अधिक मजबूत सुरक्षा और राहत प्रदान करना था।

• अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "बाल" वह पुरुष है, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम या महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। बाल विवाह की परिभाषा के मुताबिक दोनों पक्षों में से किसी एक का बाल होना आवश्यक है।

• बाल विवाह निषिद्ध, हैं और बाल पक्ष द्वारा (वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर जिला न्यायालय में याचिका दायर करके) रद्द किए जा सकते हैं। तस्करी, बल प्रयोग, छल या अनैतिक उद्देश्यों के मामलों में ये विवाह प्रारंभ से ही अमान्य होते हैं।

• दंडः संज्ञेय और गैर–जमानती अपराधों में वयस्क पुरुषों द्वारा बच्चों से विवाह करने, ऐसे विवाहों का आयोजन/संचालन/सहयोग/प्रचार करने/उपस्थित होने (माता–पिता/अभिभावकों सहित) के लिए 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और/या 1 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। महिला अपराधियों को कारावास का प्रावधान नहीं है।

• राज्य बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की नियुक्ति करते हैं, ताकि ऐसे विवाहों को रोका जा सके, साक्ष्य एकत्र किए जा सकें, जागरूकता बढ़ाई जा सके और आंकड़े पेश किए जा सकें। मजिस्ट्रेट होने वाले विवाहों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करते हैं (उल्लंघन करने पर विवाह अमान्य हो जाता है)।

बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी)

27 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी), जिसे बाल विवाह मुक्त भारत के नाम से भी जाना जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की देश भर में बाल विवाहों के उन्मूलन की एक साहसिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिशन सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5.3 के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मकसद 2030, तक बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह सहित सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है। भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित और बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 जैसे ऐतिहासिक कानूनों द्वारा समर्थित, बाल विवाह मुक्त भारत एक व्यापक सामाजिक समस्या का समाधान करता है, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों, खासकर अधिकांश मामलों में लड़कियों और विशेष रूप से हाशिए पर रहने

वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

8 अक्टूबर 2024 को रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 1234/2017– सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य–में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ने देश भर में बाल विवाह को प्रभावी ढंग से रोकने और समाप्त करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक व्यापक ढांचा और विस्तृत निर्देश जारी किए। न्यायालय ने बाल विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध के लिए विधायी संशोधनों का आग्रह करते हुए रोक लगा दी, क्योंकि यह स्वायत्तता को कमजोर करता है और अक्सर जबरन विवाह की ओर ले जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला/उप–जिला स्तर पर पूर्णकालिक समर्पित बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, जो अन्य कर्तव्यों से मुक्त हों और समन्वय, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए विशेष बाल विवाह निषेध इकाइयों की स्थापना करने का निर्देश दिया गया। सक्रिय रोकथाम उपायों में शामिल हैं:

• स्कूलों, आंगनवाड़ियों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक नेताओं को शामिल करते हुए अनिवार्य बहुक्षेत्रीय जागरूकता अभियान

• पुलिस, न्यायपालिका, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी–आधारित रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया

• जोखिमग्रस्त क्षेत्रों का डेटाबेस बनाए रखना

यह निर्णय निर्णायक रूप से सजा से हटकर रोकथाम, संरक्षण और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे ढांचा अधिक मजबूत और बाल–केंद्रित बनता है।

इस प्रकार, बाल विवाह मुक्त भारत पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना जैसी पिछली पहलों को आगे बढ़ाने का एक संजीदा प्रयास है, लेकिन यह बाल विवाह की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए अधिक एकीकृत, प्रौद्योगिकी–आधारित दृष्टिकोण पेश करती है।

100 दिवसीय अभियानः बाल विवाह के विरुद्ध एक गतिवर्धक अभियान

4 दिसंबर, 2025 को, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गंभीरता के साथ 100 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक माह एक विशिष्ट जागरूकता अभियान के लिए समर्पित है।

इसके अलावा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए, अभियान दो प्रतिष्ठित सम्मानों की शुरुआत कर रहा है:

बाल विवाह मुक्त ग्राम प्रमाण पत्रः यह प्रमाण पत्र उन गांवों/पंचायतों को दिया जाएगा, जो औपचारिक रूप से बाल विवाह को समाप्त करने और लंबे समय तक शून्य मामले दर्ज करने का संकल्प लेते हैं।

बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा पुरस्कारः बाल विवाह के मामलों में रिपोर्टिंग की दक्षता, रोकथाम की सफलता और बाल विवाह के मामलों में समग्र कमी के आधार पर मूल्यांकन किए गए शीर्ष 10 प्रदर्शनकारी जिलों को यह राष्ट्रीय उपाधि प्रदान की जाएगी। इन जिलों को आधिकारिक बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, उन्हें एक औपचारिक प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिलेगा और उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से मान्यता दी जाएगी।

राष्ट्रव्यापी अभियान का आधिकारिक शुभारंभ 4 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य शुभारंभ समारोह के साथ हुआ, जिसके साथ ही एक समन्वित राष्ट्रीय शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। यह एकजुट प्रतिबद्धता भारत के पूर्णतः बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनने के संकल्प को पुनः स्थापित करेगी।

महिला एवं महिला विकास आयोग द्वारा निर्धारित इन उपायों को लागू करने में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है। मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला स्तरीय कार्यबल गठित करें, जिसमें सीएमपीओ, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और पीआरआई शामिल हों। यह कार्यबल साप्ताहिक निगरानी करेगा और बीवीएमबी पोर्टल के ज़रिए भौगोलिक रूप से चिह्नित प्रगति रिपोर्ट पेश करेगा। यह अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बहुक्षेत्रीय समन्वय पर बल देता है।

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह प्रमुख पहल एक केंद्रीकृत, सार्वजनिक रूप से सुलभ मंच प्रदान करती है, जिसमें भारत भर में नियुक्त सभी बाल विवाह निषेध अधिकारियों की सूची दी गई है, बाल विवाह के मामलों की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में हितधारकों और नागरिकों को शामिल करने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियानों और कार्यों पर नज़र रखी जाती है।

देशव्यापी जागरूकता अभियानः एक झलक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस अभियान को पूर्ण रूप से वित्त पोषित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें एनएफएचएस–वी आंकड़ों के ज़रिए पहचाने गए 257 उच्च–मामलों वाले जिलों (वे जिले जहां बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक है) को प्राथमिकता दी गई है।

बाल विवाह रोकथाम अभियान इस समय पूरे जोर–शोर से जारी है, देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोश–ओ–खरोश और समन्वय के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के लाखों छात्रों के साथ–साथ ग्राम पंचायतों सहित अन्य प्रमुख हितधारकों ने बाल विवाह विरोधी शपथ ली है।

बाल विवाह मुक्त भारत की ओरः अब तक की प्रगति

अपनी शुरुआत से ही, बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी) मिशन ने पूरे भारत में बाल विवाहों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप प्रमुख प्रवर्तन और जागरूकता संबंधी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस प्रगति का एक मुख्य आधार बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत अनिवार्य रूप से देशव्यापी समर्पित बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की तैनाती है। राज्य स्तरीय निर्देशों के ज़रिए सशक्त इन अधिकारियों ने घर–घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने और राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन (1098) से जुड़ी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों सहित सक्रिय मदद की है। प्रवर्तन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा जारी अक्षय तृतीया का 2025 का निर्देश था, जिसने सामूहिक विवाहों के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील उच्च मामलों वाले समय को लक्षित किया। इससे निगरानी में वृद्धि हुई, जिसके नतीजतन न्यायिक निषेधाज्ञा, सामुदायिक परामर्श और एफआईआर दर्ज करके सैकड़ों बाल विवाह के मामलों को रोका गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के साथ एकीकृत इन प्रयासों से पीसीएमए के तहत दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई है, साथ ही कई गांवों में "बाल विवाह निषेध क्षेत्र" को बढ़ावा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, बीवीएमबी को वैश्विक स्तर पर, खास तौर पर यूनिसेफ से, मजबूत समर्थन मिला है, जिसके तहत यूनिसेफ ने सीएमपीओ और वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) के लिए डेटा–आधारित गतिविधियों और क्षमता–निर्माण कार्यशालाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है। एसडीजी 5.3 और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के अनुरूप, ये उपलब्धियां भारत को दक्षिण एशिया में बाल विवाह विरोधी रणनीतियों के लिए एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच निरंतर समन्वय शामिल है।

छत्तीसगढ़: बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में उम्मीद की किरण

छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लगातार दो वर्षों से, इसके 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी स्थानीय निकायों में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि सरकार के निरंतर प्रयासों, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और व्यापक जागरूकता अभियानों का परिणाम है। बालोद की इस सफलता से प्रेरित होकर, छत्तीसगढ़ अब 2028–29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

इसी राज्य में एक अन्य उल्लेखनीय मिसाल के तहत, सूरजपुर जिले ने सामाजिक सुधार और सामुदायिक जागरूकता में एक सशक्त उदाहरण पेश किया है। 17 सितंबर, 2025 को, पोषण माह 2025 के शुभारंभ के अवसर पर, जिला प्रशासन ने गर्वपूर्वक 75 ग्राम पंचायतों को "बाल विवाह मुक्त पंचायत" घोषित किया। इन पंचायतों को लगातार दो वर्षों तक बाल विवाह का एक भी मामला दर्ज न करने के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद गौरव का क्षण है और भारत के हर हिस्से के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

भारत में बाल विवाह उन्मूलन की यात्रा 19वीं सदी के सुधारों और 1929 के शारदा अधिनियम से शुरू हुई और 2006 के सशक्त बाल विवाह निषेध अधिनियम और 2024 के ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इसे और बल दिया। पिछले कुछ दशकों में इसकी व्यापकता में खासी कमी आई है। नवंबर 2024 में शुरू किया गया और इस वक्त जारी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान (मार्च 2026 तक चलने वाला) द्वारा समर्थित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इस लड़ाई में एक अहम किरदार निभा रहा है। समर्पित बाल विवाह निषेध अधिकारियों, बीवीएमबी पोर्टल की तकनीक–सक्षम रिपोर्टिंग और जमीनी स्तर पर मिली सफलताओं के ज़रिए, यह पहल रोकथाम, संरक्षण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ सहजता से एकीकृत होती है।

लाखों लोगों द्वारा इस मिशन में शामिल होने से इस दिशा में जारी महत्वपूर्ण प्रयास न केवल गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं, बल्कि सतत् विकास लक्ष्य 5.3 और एक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप भी हैं। सरकार, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की निरंतर सामूहिक कार्रवाई असमानता के इस चक्र को तोड़ने और हर बच्चे के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वायत्तता के अधिकार को सुनिश्चित करने का वादा करती है। एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ, भारत बाल विवाह से मुक्त भविष्य ज़रुर हासिल कर सकता है, जिससे लड़कियों और लड़कों की पीढ़ियां आगे बढ़ सकेंगी।

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव–2026 : सूरत के रिवरफ्रंट पर देश–विदेश के 94 पतंगबाज बने आकर्षण का केंद्र

सूरत, 10 जनवरी।

गुजरात के सूरत शहर के अडाजण रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव–2026 में देश–विदेश के कुल 94 पतंगबाजों ने भाग लिया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे।

गुजरात पर्यटन निगम, सूरत महानगरपालिका और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में सांसद मुकेशभाई दलाल की अध्यक्षता में इस 'अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव–2026' का भव्य आयोजन हुआ। इसमें 21 देशों से 45 विदेशी पतंगबाज, भारत के चार राज्यों से 20 और गुजरात के 29 पतंगबाज शामिल हुए। सभी ने अनोखी, विशाल और रंग–बिरंगी पतंगें उड़ाकर सूरत के आसमान को मनमोहक बना दिया। विभिन्न आकृतियों और आकर्षक रंगों वाली पतंगों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कुशल पतंगबाजों ने अपनी कला–कौशल से भरपूर प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर सांसद मुकेशभाई दलाल ने सूरतवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में उत्तरायण पर्व का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। पतंग उड़ाना टीमवर्क का बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें एकता का संदेश देता है। जिस तरह पतंग को ऊंचा उड़ने के लिए सही दिशा में हवा की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन में सही मार्ग पर चलने से सफलता सुनिश्चित होती है।

फूल खिलते ही बदल दें नींबू की तकदीर, ये 4 ऑर्गेनिक बूस्टर भर देंगे पेड़ में जान

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

जनवरी के मौसम में बगीचों और खेतों में नींबू के पेड़ पर फूलों की बहार दिखने लगती है. यही वह समय होता है, जब पौधे को अतिरिक्त और संतुलित पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि फूल आने के बाद अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक पोषण सही तरीके से दिया जाए, तो पौधे की ऊर्जा फल निर्माण में लगती है, जिससे उत्पादन बेहतर मिलता है.

अक्सर किसान और गार्डनिंग प्रेमी फूलों के बाद सामान्य पानी और खाद पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यही वह चरण है, जब थोड़ी सी सही देखभाल पूरी फसल की तस्वीर बदल सकती है. ऑर्गेनिक चीज़ें पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती हैं, मिट्टी में माइक्रो पोषक तत्व बढ़ाती हैं और पेड़ को लंबे समय तक प्राकृतिक ऊर्जा देती हैं. इससे फल झड़ने की समस्या भी कम होती है.

फूल आने के बाद सरसों खली सबसे असरदार ऑर्गेनिक पोषण में से एक मानी जाती है. यह मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर की कमी पूरी करती है. 250 ग्राम सरसों खली को 5 लीटर पानी में 48 घंटे भिगोकर छान लें. महीने में एक बार यह घोल पौधे की जड़ों में डालने से नींबू की साइज बड़ी और छिलका चमकदार बनता है.

केले में पोटैशियम भरपूर होता है, जो फूल के बाद फल विकास के लिए जरूरी है. 3–4 पके केले को 4 लीटर पानी में मसलकर 24 घंटे रखें. इसे छानकर 15–20 दिन में एक बार पौधे में डालें. पोटैशियम से फल की कोशिकाएं तेजी से विकसित होती हैं, जिससे नींबू रसदार और बड़े आकार में उगते हैं. यह घोल पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है.

फूल के बाद 1–2 किलो अच्छी तरह सड़ी गोबर खाद को पौधे के तने से 1 फुट दूर गोलाई में मिट्टी में मिलाएं. गोबर खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, नमी संतुलन सुधारती है और लाभकारी सूक्ष्म जीव सक्रिय करती है. इससे फल झड़ने की समस्या कम होती है और नींबू गुच्छों में ज्यादा संख्या में लगते हैं. 45 दिन के अंतर पर दोहराएं.

मछली अमीनो एसिड एक नेचुरल ग्रोथ बूस्टर है, जो फूल के बाद नींबू की ग्रोथ तेज करता है. 10 मिली FAA को 1 लीटर पानी में मिलाकर 20–25 दिन में एक बार स्प्रे करें या मिट्टी में डालें. इससे फल का वजन बढ़ता है, रस की मात्रा बेहतर होती है और पेड़ लंबे समय तक स्वस्थ रहता है.

अधिकतम परिणाम के लिए 15 दिन के अंतर पर पोषण बदलकर दें: पहले FAA स्प्रे, फिर केले का घोल, फिर सरसों खली घोल. यह चक्र 45–60 दिन तक अपनाने से नींबू बड़े क्लस्टर में उगते हैं. ध्यान रखें कि अधिक खाद तने से दूर दें, ताकि जड़ें बिना जलन पोषण ग्रहण कर सकें. सुबह या शाम का समय बेहतर माना जाता है.

इतिहास के पन्नों में 11 जनवरीः भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में निधन हो गया। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ।हालांकि उनके निधन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल अभी भी मौजूद हैं। उनके निधन के बाद भारत में 12 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया गया और नई दिल्ली स्थित विजय घाट पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

अन्य अहम घटनाएंः– 2020– केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' और 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' का उद्घाटन किया।

2010 –भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के दो सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है।

2009 – आईटी कम्पनी सत्यम को बचाने के लिए सरकार ने तीन नामित सदस्यों की नियुक्ति की। अचंता शरत कमल ने –70वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का ख़िताब जीता।

2001 – भारत और इंडोनेशिया के मध्य पहली बार रक्षा समझौता।

1999 – शहरी भूमि सीमा क़ानून निरस्त।

1998 – लुईस फ़रेचेट (कनाडा) सं.रा. संघ की उपमहासचिव नियुक्त।

1995 –कार्टहेना, कोलम्बिया में विमान दुर्घटना में 52 व्यक्ति मारे गये।

1993 – सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्धविराम का उल्लघंन करने के लिए चेतावनी दी।

1973 – बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की।

1970 – अलग हुआ बियाफ्रा राज्य नाईजीरियाई सरकार के हमले को नहीं झेल पाया और आत्म समर्पण कर दिया।

1962 – हिमस्खलन से पेरुवियन एंडेस गाँव में तीन हज़ार मौतें हुई।

1955 – भारत के अख़बारी काग़ज़ का उत्पादन प्रारम्भ हुआ।

1943 – ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया।

1942 – द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अधिकार किया।

1866 – आस्ट्रेलिया जाते समय लंदन नामक जहाज़ में हुई दुर्घटना में 231 व्यक्ति डूब गये।

1753 – स्पेन नरेश जोकिन मुरात ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ दिया।

1681 – ब्रैडेनबर्ग और फ़्राँस के बीच रक्षा गठबंधन हुआ।

1613 – जहाँगीर ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को सूरत में कारख़ाना लगाने की अनुमति दी।

जीमेल में आया जेमिनी–पावर्ड एआई इनबॉक्स, ईमेल होंगे और स्मार्ट

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए Gemini–आधारित नए एआई फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इनमें सबसे खास है AI Inbox, जो यूजर्स को ईमेल से जुड़ी जरूरी जानकारी, टू–डू लिस्ट और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेगा।

ये नए फीचर्स फिलहाल अमेरिका में जीमेल यूजर्स और Google AI Pro व Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू किए गए हैं। कंपनी आने वाले महीनों में इसे अन्य भाषाओं और देशों में भी लॉन्च करेगी।

गूगल के मुताबिक, AI Inbox एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। यह खुद पहचान करेगा कि कौन–से ईमेल ज्यादा जरूरी हैं, किन लोगों से आप अक्सर बात करते हैं और किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह पूरा प्रोसेस यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से किया जाएगा।

AI Inbox यूजर्स को लंबे ईमेल थ्रेड्स का छोटा और आसान सार (Summary) भी देगा ताकि जरूरी बातें तुरंत समझ में आ सकें। साथ ही, अगर यूजर अपने इनबॉक्स से कोई सवाल पूछता है तो Gmail Gemini AI की मदद से सीधा और आसान जवाब देगा।

अब सभी यूजर्स के लिए 'Help Me Write' फीचर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे ईमेल लिखना, सुधारना और प्रोफेशनल बनाना आसान हो जाएगा।

इसके अलावा नए Suggested Replies फीचर से एक क्लिक में सही और प्रोफेशनल रिप्लाई मिल सकेगा।

गूगल ने बताया कि आज दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं और एआई पहले से ही स्पैम रोकने और स्मार्ट रिप्लाई जैसी सुविधाओं में अहम भूमिका निभा रहा है।

भारत की पहली डिजिटल जनगणना का शेड्यूल जारी, पहला चरण अप्रैल से सितंबर तक

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण के टाइमलाइन को लेकर अधिसूचना हाल ही में जारी कर दी है। इस जनगणना में घरों की गिनती और हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ये जनगणना इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच चलेगी। ये 30 दिनों की अवधि की रहेगी, जिसे हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।

केंद्र ने अपनी अधिसूचना में कहा, "जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 और 17।, जनगणना नियम, 1990 के 6। और 6क के साथ पढ़े जाने वाले और 7 जनवरी, 2020 की अधिसूचना को रद्द करते हुए, सिवाय उन कामों के जो इस रद्दीकरण से पहले किए गए या नहीं किए गए, जनगणना 2027 के हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन में स्व–गणना का विकल्प होगा। अधिसूचना में ये भी कहा गया, "...ये प्रक्रिया 30 दिनों के घर–घर हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों में किया जाएगा।"

ये जनसंख्या गणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी – हाउसलिस्टिंग और आवास जनगणना। पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 और दूसरा चरण 28 फरवरी, 2027 को होगी। इसमें 1 मार्च, 2027 को रात 12 बजे को संदर्भ तारीख माना जाएगा (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और बर्फ से ढके क्षेत्रों और जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गैर–समकालिक क्षेत्रों को छोड़कर)। नवीनतम जनगणना में जाति पहचान को भी शामिल किया जाएगा।

दरअसल, यह जनगणना 10 साल में होती है और इसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण जनगणना 2021 में देरी हुई थी। पिछले साल 12 दिसंबर को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.2 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया, जनगणना में लगभग 30 लाख फील्ड अधिकारी

शामिल होंगे। पहली डिजिटल जनगणना होने के नाते, इसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी उद्देश्यों के लिए एक केंद्रीय पोर्टल का उपयोग शामिल होगा, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा सुनिश्चित होंगे।

सरकार ने पिछले महीने कहा था कि जनगणना डेटा का प्रसार बहुत बेहतर होगा और यूजर्स के अनुकूल तरीके से किया जाएगा, ताकि नीति निर्माण के लिए आवश्यक मापदंडों पर सभी सवालों के जवाब सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगे। जनगणना–एज–ए–सर्विस मंत्रालयों को स्वच्छ, मशीन–पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में डेटा प्रदान करेगा।

पूरी प्रक्रिया को वास्तविक समय के आधार पर प्रबंधित और निगरानी करने के लिए एक समर्पित पोर्टल, जिसका नाम जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल है, विकसित किया गया है। जनता अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 30–दिवसीय हाउसलिस्टिंग चरण शुरू होने से 15 दिन पहले जनगणना ऐप या पोर्टल के जरिये स्वयं गणना कर सकती है। डिजिटल जनगणना के लिए उपयुक्त सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

जनगणना प्रक्रिया में प्रत्येक घर का दौरा करना और हाउसलिस्टिंग और आवास जनगणना और जनसंख्या गणना के लिए अलग–अलग प्रश्नावली भरना शामिल है। जनगणना करने वाले, जो आमतौर पर सरकारी शिक्षक होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा जनगणना का फील्डवर्क करेंगे।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से 'विकसित भारत' के निर्माण का किया आह्वान

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में देश के युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी संभालने का आह्वान किया।

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि देश के 140 करोड़ नागरिक मिलकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करें, जिसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। उन्होंने कहा, "आप देश का भविष्य हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से उन्होंने स्पष्ट कहा था कि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार नहीं, बल्कि देश के सभी 140 करोड़ नागरिक मिलकर करेंगे और इसमें युवा मशाल वाहक होंगे।"

मांडविया ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने कौशल, ऊर्जा व नवाचार के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'आप जैसे युवा देश का भविष्य हैं।' हमें 'विकसित भारत' का राही अपने देश के युवाओं को बनाना है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की

स्वतंत्रता भारी बलिदानों की कीमत पर मिली है। उन्होंने युवाओं से इतिहास से प्रेरणा लेकर देश के पुनर्निर्माण और एक सशक्त, महान भारत के निर्माण के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

श्री डोभाल ने कहा, "आज का स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए अपार कष्ट सहे, अपमान झेला और असहायता के दौर देखे। गांव जलाए गए, सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया और मंदिरों को लूटा गया। यह इतिहास आज के युवाओं के लिए एक चुनौती है, जो उन्हें देश को फिर से उसके गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने की प्रेरणा देता है।"

'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0' शनिवार से शुरू होकर 12 जनवरी तक भारत मंडपम में होगा। इसका पहला संस्करण जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था। यह संवाद भारत की विकास यात्रा में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

भाषा संस्कृति को जीवित रखती है, हिन्दी के माध्यम से विरासत का प्रसार लक्ष्यः विदेश राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

दुनियाभर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के इस दिवस की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान–प्रदान सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2006 में आज ही के दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से हर वर्ष 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशन भी प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाते हैं। विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भाषा संस्कृति को जीवित रखती है और इसका उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रसार करना है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कल विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय प्रवासी भारतीयों को हिंदी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विश्व भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सौ से अधिक देशों के लगभग 770 संस्थानों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि हिंदी दिवस पर विश्व भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकार ने लॉन्च किया 'कर्मयोगी क्लासरूम', अब एआई से होगी अफसरों की स्मार्ट ट्रेनिंग

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों की ट्रेनिंग और क्षमता विकास को और बेहतर बनाने के लिए 'कर्मयोगी क्लासरूम' की शुरुआत की है। यह iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया एआई–आधारित फीचर है, जो अधिकारियों को ज्यादा इंटरएक्टिव, पर्सनलाइज्ड और जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देगा। केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म अधिकारियों को "नियमों से भूमिकाओं की ओर" ले जाने में मदद कर रहा है, जिससे वे अपने काम को ज्यादा स्पष्टता, जिम्मेदारी और परिणामों पर फोकस के साथ कर सकें।

उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर अब एआई सारथी, एआई ट्यूटर और एआई आधारित कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग, तेजी से प्लानिंग और बेहतर कार्य निष्पादन संभव हो पाया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इसे हाइब्रिड मॉडल बताते हुए कहा कि इससे शासन व्यवस्था को ज्यादा मजबूत, जवाबदेह और भविष्य के लिए तैयार बनाया जा सकेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक चुनौतियां, नागरिकों की अपेक्षाएं और तकनीक लगातार बदल रही हैं, इसलिए सीखना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि मिशन कर्मयोगी की शुरुआत पहले सिविल सेवकों के लिए हुई थी, जिसे अब सभी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों तक विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही कर्मयोगी प्रारंभ पहल के तहत नए भर्ती होने वाले अधिकारियों को भी सेवा की शुरुआत से ही ट्रेनिंग दी जा रही है।

जानिए क्यों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह?

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल जनवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषयों में जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सरकारी एजेंसी है। भारत में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों के बीच सड़क सुरक्षा नियमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया है। इसमें वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रक ड्राइवरों की फ्री जांच और उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

1989 में पहला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया और मनाया गया था। इस वर्ष 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में परिवहन एवं यात्रा करते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व पर ज़ोर दिया जाएगा।

वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स, 2018 ने 199 देशों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा है। भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में कार दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1.50 लाख थी, जो 2017 में घटकर 1.47 लाख हो गई। हालांकि, अगले वर्ष, 2018 में, यह बढ़कर 1.49 लाख हो गई। .

इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा में सुधार करना था। राज्य परिवहन मंत्रियों के समूह की कई सिफारिशों पर विचार किया गया। इनमें नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाना, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाना, दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के लिए न्यूनतम मुआवजे में वृद्धि

करना आदि शामिल हैं।

कोविड–19 और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान वैश्विक स्थिरता के बावजूद, मार्च और जून के बीच सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या 29,415 तक पहुंच गई है।

सुरक्षा में सुधार करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों में जमीनी स्तर पर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और संबंधित हितधारकों (कॉर्पोरेट्स, पीएसयू, एनजीओ आदि) से अनुरोध किया है कि वे सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करें और प्राथमिक उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण, सड़क सम्बंधी नियमों एवं कानूनों के बारे जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करके इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों, कार्यशालाओं तथा हिमायती कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यातायात नियमों का पालन करके हम ना सिर्फ स्वयं की जान बचा पायेंगे बल्कि अन्य राहगीरों की भी रक्षा कर पायेंगे।

यूआईडीएआई ने लॉन्च किया 'उदय', अब आधार सेवाओं की जानकारी होगी और आसान

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार सेवाओं की जानकारी को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए आधार का नया मैस्कॉट 'उदय' (Udai) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं को समझने में आसानी देना और संचार को अधिक दोस्ताना बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि यह मैस्कॉट आधार से जुड़े अपडेट, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, चुनिंदा जानकारी साझा करने, नई तकनीक के इस्तेमाल और जिम्मेदार उपयोग जैसी बातों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि इस मैस्कॉट को डिजाइन और नाम देने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें देशभर से 875 प्रविष्टियां आईं, जिनमें छात्रों, प्रोफेशनल्स और डिजाइनर्स ने भाग लिया।

इस प्रतियोगिता के जरिए UIDAI ने यह संदेश दिया कि लोगों की भागीदारी से ही भरोसा और स्वीकार्यता बनती है। चयन के लिए पारदर्शी और बहु–स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई।

विजेता प्रतिभागी

मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता

पहला पुरस्कारः अरुण गोकुल (त्रिशूर, केरल)

दूसरा पुरस्कारः इदरीस दवईवाला (पुणे, महाराष्ट्र)

तीसरा पुरस्कारः कृष्णा शर्मा (गाजीपुर, उत्तर प्रदेश)

मैस्कॉट नाम प्रतियोगिता

पहला पुरस्कारः रिया जैन (भोपाल)

दूसरा पुरस्कारः इदरीस दवईवाला (पुणे)

तीसरा पुरस्कारः महाराज सरन चेल्लापिल्ला (हैदराबाद)

UIDAI के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में 'उदय' मैस्कॉट का अनावरण किया और विजेताओं को सम्मानित किया।

UIDAI के मुताबिक, यह पहल आधार से जुड़ी जानकारी को एक अरब से ज्यादा भारतीयों के लिए आसान, समावेशी और लोगों के करीब लाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

सस्ती और घटिया विदेशी चाय पर लगेगा ब्रेक, अब हर खेप की होगी 100 फीसदी गुणवत्ता जांच

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

देश की चाय उद्योग को लंबे समय से जिस समस्या ने परेशान कर रखा था, उस पर अब सख्ती से कार्रवाई की तैयारी हो गई है. भारत में सस्ती और घटिया गुणवत्ता वाली आयातित चाय की बढ़ती आवक को रोकने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब विदेश से आने वाली चाय की हर खेप की 100 प्रतिशत गुणवत्ता जांच की जाएगी, ताकि देश के बाजार में खराब गुणवत्ता की चाय न पहुंच सके और घरेलू चाय उद्योग को नुकसान से बचाया जा सके.

चाय उद्योग लंबे समय से यह शिकायत कर रहा था कि पड़ोसी देशों से सस्ती और कम गुणवत्ता वाली चाय बिना पर्याप्त जांच के भारत में आ रही है. इससे न केवल बाजार में भारतीय चाय की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय चाय, खासकर दार्जिलिंग जैसी प्रीमियम चाय की पहचान भी प्रभावित हो रही है. इन्हीं चिंताओं को देखते हुए बोर्ड ने अब आयात नीति को और कड़ा करने का निर्णय लिया है.

बिजनेस साइन की खबर के अनुसार, चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष सी. मुरुगन ने कोलकाता में आयोजित टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की द्विवार्षिक आम बैठक के दौरान यह भरोसा दिलाया कि अब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने कहा कि बोर्ड आयातित चाय की 100 प्रतिशत जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है. इसके लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा. इसके बाद कानूनी राय ली जाएगी और फिर वाणिज्य मंत्रालय से अंतिम मंजूरी प्राप्त की जाएगी.

बोर्ड के अनुसार नेपाल और वियतनाम जैसे देशों से सस्ती और कम गुणवत्ता वाली चाय भारत में पहुंच रही है. ये चाय कीमत में भले ही सस्ती हो, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से भारतीय मानकों पर खरी नहीं उतरती. ऐसी चाय के कारण घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता है और किसानों व बागान मालिकों की आय पर भी असर पड़ता है.

चाय बोर्ड अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चाय के प्रचार पर भी जोर देगा. बोर्ड की योजना है कि अलग–अलग देशों में भारतीय चाय की ब्रांडिंग और सामान्य प्रचार को बढ़ाया जाए, ताकि निर्यात को मजबूती मिले और वैश्विक बाजार में भारतीय चाय की पहचान और मजबूत हो.

पार्यावरण में मौजूद जलवाष्प एरोसॉल्स से कहीं अधिक गर्म करता है वातावरण

नई दिल्ली, 10 जनवरी।

वातावरण में मौजूद जलवाष्प वातावरण को एरोसॉल्स (गैस में बारीक ठोस या तरल कण) की तुलना में कहीं अधिक गर्म करता है। एटमॉस्फेरिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताया गया कि जलवाष्प और एरोसॉल्स की परस्पर क्रियाएं वातावरण के विकिरण संतुलन को गहराई से प्रभावित करती हैं और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून सहित क्षेत्रीय जलवायु पर निर्णायक असर डालती हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एरीज), नैनीताल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ किए गए अध्ययन में पाया कि भारत. गंगा के मैदान को एक वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां वायुमंडल में पहुंचने वाली जलवाष्प की अधिक मात्रा तापमान बढ़ाने में सहायक होती है।

उन्होंने बताया कि जब एरोसॉल्स की मात्रा कम होती है तब जलवाष्प वायुमंडल और पृथ्वी की सतह दोनों को अधिक प्रभावित करता है। खासकर, ग्रीष्म मानसून के लिए। उन्होंने बताया कि 'एरोसॉल्स' सूर्य की रोशनी को कुछ हद तक रोक लेते हैं, जिससे तापमान पर असर पड़ता है जबकि 'जलवाष्प' गर्मी को अपने अंदर रोक लेती है,

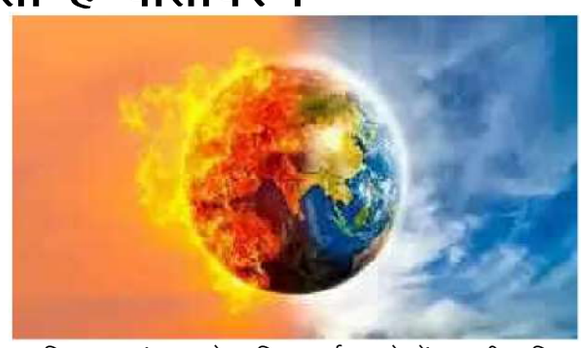

इसलिए वायुमंडल को अधिक गर्म करने में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है।

अध्ययन में बताया गया कि जलवाष्प भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके परिणाम बताते हैं कि जलवाष्प और एरोसॉल्स दोनों को साथ लेकर ही विश्वसनीय जलवायु पूर्वानुमान और नीतिगत निर्णय किए जा सकते हैं।

एआरआईएस के डॉ. उमेश चंद्र दुमका और आईआईए के डॉ. शांतिकुमार एस. निंगोमबम ने पश्चिमी मैसेडोनिया विश्वविद्यालय के दिमित्रिस जी. कास्काउटिस, आरईपी सोतिरोपोलू और ई. टैगारिस तथा सोका विश्वविद्यालय के डॉ. प्रदीप खत्री के साथ मिलकर यह शोध किया।